पना शहर

प्रथम महिला शिक्षिका व स्त्रियों के अधिकारों के लिए सतत संघर्ष करने वाली एवं वंचित वर्गों की शिक्षा और समानता की प्रबल समर्थक माता सावित्रीबाई फुले की जयंती पर व शत-शत नमन। — डा. दिनेश शर्मा, डिप्टी सीएम उप्र

योजनाओं का लाभ सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा रही है। — योगी आदित्यनाथ, सीएम, उप्र

नई दिल्ली । शुक्रवार • 4 जनवरी • 2019 | राष्ट्रीय सहारा | www.rashtriyasahara.com

प्रगति मैदान में ज्ञान का कुंभ कल से

27वां दिल्ली विश्व पुस्तक मेला

नई दिल्ली (एसएनबी)। शनिवार से दिल्ली के प्रगति मैदान में ज्ञान का कुंभ सजेगा। 13 जनवरी तक चलने वाले 27वें नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर करेंगे। इस मौके पर शारजाह के राजकीय संबंध विभाग के कार्यकारी अध्यक्ष एवं वहां के शाही परिवार के सदस्य शेख फहीम बिन सुल्तान अल कासिमी मुख्य अतिथि होंगे, जबकि शारजाह पुस्तक प्राधिकरण के अध्यक्ष अहमद बिन रक्काद अल आमरी अतिथि होंगे। यह जानकारी पुस्तक मेले के आयोजक नेशनल बुक ट्रस्ट (एनबीटी) के अध्यक्ष बलदेव भाई शर्मा ने दी। इस मौके पर इंडिया ट्रेड प्रमोशन

बलदेव भाई शर्मा ने बताया कि थीम के अनुसार हॉल नम्बर सात में विशेष मंडप बनाया गया है जिसमें दर्शकों को समझाने के लिए संकेत भाषा के दुभाषिए मौजूद रहेंगे। यहां ब्रेल पुस्तकें, स्पर्शनीय पुस्तकें, मूक पुस्तकें, ऑडियो पुस्तकें होंगी। इस बार यहां पर दिव्यांगता के बावजूद अपनी पहचान बनाने वाले लोगों पर बनायी गयी डाक्यूमेंट्री फिल्मों का भी प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेले

...त : सत्याग्रह की ...भर के डाक्टर

संसदीय कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया था। इसी कमेटी के सदस्य और आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. शांतनु सेन ने पत्रकारों के सामने यह घोषणा की और कहा कि सदन के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कमेटी ने विधेयक में 24 संशोधन की सिफारिश की थी लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के काउंसिल हॉल में अकादमिक काउंसिल (एसी) के सदस्य बुधवार रातभर डटे रहे। उनका विरोध प्रदर्शन बृहस्पतिवार को भी जारी रहा। करीब 18 महीने बाद बुधवार को आयोजित की गई परिषद में हंगामा हुआ था और किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पाई थी। बैठक स्थगित होने के बाद से एसी मेम्बर्स धरने पर बैठ गये थे।

परिषद के सदस्य प्रो. हंसराज सुमन ने बताया है कि विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से संवाद और समाधान की दिशा में अभी तक कोई पहल नहीं हुई है। उनका कहना है कि एसी बैठक में भारत के राजपत्र में 18 जुलाई 2018 को प्रकाशित यूजीसी रेगुलेशन को विश्वविद्यालय के अधिनियमों में परिवर्तित करके पारित किया जाना था। वहीं 17 सितम्बर 2018 को यूजीसी रेगुलेशन के संशोधन व परिवर्द्धन और उसके आधार पर विश्वविद्यालय के अधिनियमों में परिवर्तन के लिए एक हाई पावर ऑर्डिनेंश अमेंडमेंट कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी ने दो महीने में बारह बैठकें कर 28 नवम्बर को अपनी रिपोर्ट जमा कर दी थी। रिपोर्ट में दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित अधिनियमों में जरूरी परिवर्तन और परिवर्द्धन किये थे, जबकि 2 जनवरी को आहूत एकेडेमिक कांउन्सिल की बैठक में ऑर्डिनेंशअमेंडमेंट कमेटी की रिपोर्ट एजेंडे से गायब थी। परिषद के सदस्य इसी का विरोध कर रहे हैं।

... (सीबीएसई) आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस को इलेक्टिव कोर्स के रूप में शुरू करने की तैयारी कर रहा है। यह कोर्स कक्षा 8, 9 व 10 में स्किल सब्जेक्ट के रूप में शुरू करने का विचार है। पाठ्यक्रम को शुरू करने का उद्देश्य स्कूली छात्रों को भविष्य को आकार देने वाली तकनीकों में पारंगत बनाना है।

सीबीएसई के एक अधिकारी ने बताया कि इसे स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का विचार नीति आयोग की एक बैठक से आया था, जिसपर बोर्ड की ओर से भी सकारात्मक पहल की गई है। अधिकारी ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा एनालिटिक्स और वैश्विक स्तर पर एक बड़ा प्रभाव बनाने वाली प्रौद्योगिकियों के साथ, यह महत्वपूर्ण है कि बोर्ड अपने पाठ्यक्रम को आधुनिकतम घटनाओं के बराबर रहने के लिए आधुनिकीकरण करे। इसी को ध्यान में रखते हुये यह पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा।

... सरकार : डा. उदित राज

नई दिल्ली (एसएनबी)। भाजपा सांसद डॉ उदितराज ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार राजधानी के विकास को लगातार बाधित कर रही है। प्रेस कॉफ्रेंस में उन्होंने घेवरा ओवरब्रिज, किराड़ी एवं नरेला में प्रस्तावित योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार जानबूझकर इनमें रोड़े अटका रही है। मेट्रो के चौथे चरण के मुद्दे पर उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मेट्रो के लाभ से वंचित कर रहे हैं।

भूमि अधिग्रहण न होने के चलते लटकी कई योजनाएं

भाजपा सांसद ने कहा कि वर्ष 2015 से दिल्ली सरकार उनके इलाके की योजनाओं को शुरू नहीं होने दे रही है, जबकि सभी योजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन इनके लिए दिल्ली सरकार के विभागों की भी मंजूरी जरूरी है। उन्होंने किराड़ी रेलवे क्रासिंग नंबर-12, घेवरा क्रासिंग-18 सी, रोहिणी जोन एवं नरेला मण्डी क्रासिंग 16 का जिक्र करते हुए कहा कि यह योजनाएं 282.70 करोड़ रुपए की हैं। इनके लिए जमीन का अधिग्रहण होना है। भूमि अधिग्रहण की मुआवजा राशि 111.82 करोड़ दिल्ली सरकार को देनी है। प्रोजेक्ट के लिए केंद्र 177 करोड़ की राशि स्वीकृत कर चुका है।

उन्होंने दिल्ली सरकार को प्रस्ताव भेजा था। मुख्यमंत्री कार्यालय से उन्हें जवाब मिला है कि जमीन अधिग्रहण का पैसा भी केंद्र को ही देना होगा। दिल्ली सरकार के इस अड़ियल रुख के चलते प्रोजेक्ट लटके हुए हैं। इन प्रोजेक्टों के पूरा होने से आसपास के गांवों के लोगों को काफी लाभ मिलेगा। मेट्रो के चौथे चरण को लेकर भी केजरीवाल ने अड़ंगा फंसा दिया है। केजरीवाल सरकार की अड़ंगे की वजह से फिलहाल गांवों को मेट्रो से जोड़ने की योजना खटाई में पड़ गयी है।

... लाख से ज्यादा की रकम निकल ली।

जुबिलैंट फूडवर्क्स लिमिटेड
CIN: L74899UP1995PLC043677
पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट 1A, सेक्टर-16A, नोएडा – 201301 (उ.प्र.)
दूरभाष: +91-120-4090500, फैक्स: +91-120-4090599
ई-मेल: investor@jubifood.com
वेबसाइट: www.jubilantfoodworks.com

सूचना

सेबी (सूचीकरण दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) अधिनियम, 2015 के अधिनियम 29 एवं 47 के प्रावधानों के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मण्डल की बैठक **बुधवार, जनवरी 30, 2019,** को दिसम्बर 31, 2018 को समाप्त तिमाही एवं नौ महीनों के अनअंकेक्षित एकल वित्तीय विवरण पर विचार तथा स्वीकृति हेतु आयोजित की जाएगी।

उपरोक्त निर्देशन कंपनी की वेबसाइट www.jubilantfoodworks.com के साथ-साथ स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

कृते जुबिलैंट फूडवर्क्स लिमिटेड
हस्ता/-
दिनांक : जनवरी 03, 2019 — मोना अग्रवाल
स्थान : नोएडा (उप्र) — कम्पनी सचिव

सूचना

[illegible]

डॉ. रमेश कुमार बने एनडीएमसी के मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी

राजधानी में वायु प्रदूषण अब भी गंभीर श्रेणी में